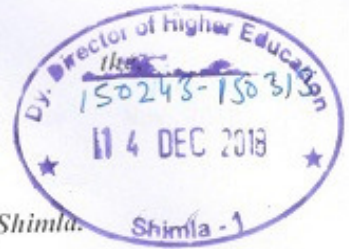


No: Shiksha-Shimla(G-1) Estimate-
O/O the Dy. Director Higher Education,
Shimla, District Shimla-01

Dated: Shimla-171001



To

All the Principal/Headmaster,
GSSSs/GHSs Chopal Constituency Distt. Shimla.

Sub:-

Report on news cuttings regarding scam of Rs. ~~4.00~~ crore in/r/o
construction of school building.

Memo,

With reference to Directorate of Higher Education Himachal Pradesh office letter No. EDN-H(9)3-7/2009-10 (A.A.&E.S.) dated 03.11.2018 vide which photocopy of news cutting published in News paper "Divya Himachal" dated 26.10.2018 from Private Secretary to the Secretary (Education) to the Govt. of HP has been received in this office on the above cited subject. (Copy enclosed).

In this regard, it is directed that name of such school in Chopal constituency alongwith detailed report may be sent to this office within 02 days if above noted scam of amount is appeared so, that same could be sent to the higher authority for further necessary action.


Dy. Director Higher Education,
Shimla, District Shimla-01

Endst. No. Even dated: Shimla-171001

Copy forwarded to:-

1. The Director of Higher Education H.P. Shimla-01 for information please.


Dy. Director Higher Education,
Shimla, District Shimla-01

शिमला के प्रत्याशी पर कल चर्चा करेगी कांग्रेस

चुनावी रणनीति बनाने के लिए जुटेगे पदाधिकारी, वर्तमान सांसद की खासियों पर होगा मंथन

शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के दावेदारों को लेकर मुख्यालय के शिमला में मंथन किया जाएगा। शिमला से कई दावेदार हैं, जिनके नामों पर चर्चा होगी और अलग-अलग प्रेशों के लोग अपने-अपने नेताओं के नाम सुझाएंगे। वैसे इस चर्चा पर अंतिम मुहर आलाकमान ने ही लगाती है, परंतु फिर भी प्रार्थी की प्रभारी रजनी पटिल सभी से उनका फीडबैक लेना चाहती हैं। शिमला के बाद रोप तीन लोकसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर इस तरह का मंथन किया जाएगा, जिसके बाद एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार सभी को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में कांग्रेस प्रभारी संभावित नामों का चिह्न करने के साथ उनके गुण व दोष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगी। शिमला में होने जा रही इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए व्यापक रणनीति बनेगी।

उन्नीस दूरमीठवालों के नामों के अलावा शक्ति कार्यक्रम का फीडबैक भी लिया जाएगा। इसमें जाना जाएगा कि अभी तक कितने लोगों ने यहां पर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसके अलावा इस बैठक में जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा होगी जिसमें देखा जाएगा कि अभी तक कांग्रेस को इसमें कितनी सफलता मिली है।

केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भी मंथन होगा ताकि उन बातों को कांग्रेस अपने प्रचार अभियान में शामिल कर सके। इसके साथ यहां पर पूर्व कमेटीयों के गठन व कार्यकर्ताओं की सहभागिता पर भी विचार होगा। भाजपा के मौजूदा सांसद द्वारा शिमला संसदीय क्षेत्र में अब तक

वर्षों के अनुभव नहीं किए गए कार्यों पर भी यहां चर्चा होगी, जिनमें कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी। बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी विधायक नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्रीराम सिंह के अलावा दूसरे कदमर नेता भी उपस्थित रहेंगे जिनसे चर्चा की जाएगी।

यहां तीन दिन रहेंगी प्रभारी रजनी पटिल

रजनी पटिल यहां पर तीन दिवसीय दौर पर आ रही हैं। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस पर से मुख्यालय मुख्या को हटवाने की विरोधी शक्ति को कोशिशें दिखाने का काम साबित हुई है। तीन दिन के लिए रजनी पटिल का यह दौर इसी बात का संकेत है। उनके जाने पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अभी राहुल गांधी ने दूसरे राज्यों में भी अभियान को नहीं हटवाया है, लिहाजा हिमाचल में भी ऐसा नहीं किया गया है।

स्कूल भवन निर्माण में चार करोड़ का घोटाला

वर्ष 2004 में बजट मिलने के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम, कौन डकार गया र

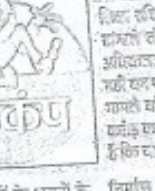
हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे हैं, लेकिन इस बार यह सवाल किसी शिक्षक नहीं, बल्कि ऑफिस में बैठने वाले बाबुओं पर उठे हैं। हरानी की बात है कि वर्ष 2004 के बाद स्कूलों के नए भवन के लिए बजट मिलने के बावजूद एक ईंट भी भवन निर्माण के लिए नहीं लग पाई है।

हरानी की बात है कि करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार परदेस सार्व में बिलों व हर ब्लॉक को दे चुकी है। राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि इतने सालों से जो बजट राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत किया गया, वह स्कूल निर्माण पर खर्च ही नहीं हो पाया।

- 15 साल से एक ईंट नहीं लगा पाया शिक्षक
- राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को बिना जांच के शर्तों
- श्रीराम ने शक्ति कार्यकर्ता

राज्य सरकार ने स्कूल निर्माण के नाम पर प्रदेस सार्व से अभी तक चार करोड़ के घोटाले की आशंका लगाई है। इतने बड़े घोटाले के बाद सरकार भी हैरान है कि आखिर इतना साफ बजट कैसे खर्च नहीं किया गया व इसकी जानकारी अभी तक विभाग में भी क्यों

हमलवा नहीं है। सरकारी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए अभी तक कितना बजट जिला और ब्लॉक अफसरों को दिया गया, इसकी रिपोर्ट मंगवा ली गई है। शिक्षा विभाग को प्रदेस सार्व की रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में निर्माण को बतला होगा कि स्कूल



निर्माण का पैसा किस ऑफिस अफसर के पास खतरा आने नहीं है बिला उपनिदेशक, ब्लॉक ऑफिस रिपोर्ट इस दौरान तैयार करवाई व टील शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों में आ सकते हैं।

शिक्षा सचिव ने वापस भेजा केस

उपलब्ध करवाई जानकारी, गृह विभाग देखेगा आगे की प्रक्रिया

उपलब्ध करवाई जानकारी, गृह विभाग देखेगा आगे की प्रक्रिया

कि आखिर सीबीआई को इसे क्यों सीया गया है। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग ने इस पर जवाब दिया है कि उपलब्ध जानकारी न केवल प्रदेस से जुड़ा है, बल्कि इसमें दूसरे राज्यों की एजेंसियां भी शामिल हैं। बाहरी राज्यों की संस्थाओं के इसमें शामिल होने के चलते राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच करना संभव नहीं है।

सीबीआई को यह मामला सीया गया है। इस जवाब के साथ शिक्षा सचिव की ओर से गृह विभाग को मामला भेज दिया गया है। सीबीआई को जांच देने से पहले सरकार ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी, जिस पर एक पारंपरिक सीबीआई की तरफ से शक को भेजा गया।



शिक्षा विभाग ने इसमें जरूरी जानकारी देकर इसे वापस कर दिया है। इसमें एफआईआर का भी एक मामला है, जिसे लेकर अभी फैसला लिया जाना है। छात्रवृत्ति घोटाला 215 करोड़ रुपए का बताया जाता है।

11.04.2004 10:00 AM